क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुपी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

दैनिक
क्रांति समय

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्स्योरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुपी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 243, शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

पूर्व विधायक रामवीर शौकीन अस्पताल से फरार

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आया नीरज बवानिया का मामा रामवीर शौकीन बुधवार को अस्पताल से फरार हो गया, जिसे बागपत पुलिस यहां लेकर आई थी। उसे जमानत के लिए बृहस्पतिवार को अदालत में पेश करना था। उससे पहले उसे सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भर्ती कराया गया था। इस मामले में बागपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन पुलिसकर्मियों - कांस्टेबल चमन सिंह, कांस्टेबल सुंदर और कांस्टेबल राजकुमार शर्मा- को निलंबित कर दिया क्योंकि इन्हीं की कस्टडी से रामबीर शौकीन फरार हुआ है। पुलिस के मुताबिक रामवीर शौकीन दिल्ली का पूर्व विधायक है और कुख्यात डॉन नीरज बवानिया का रिश्ते में मामा लगता है। उस पर नीरज बवानिया के साथ अपराध में साथ देना और एके-47 जैसा हथियार रखने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शौकीन को गिरफ्तार किया था। रामवीर की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस ने कुख्यात नीरज बवानिया को गिरफ्तार किया था। उसी दौरान पुलिस को एके-47 राइफल मिली जो बागपत पुलिस से छीनी हुई थी।

स्वच्छता दूत-54: फेसबुक पर ग्रुप बनाकर राजीव मिटा रहे दिल्ली की गंदगी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया के इस दौर में एक शख्स ने इसे ही गंदगी के खिलाफ हथियार बना दिया। फेसबुक पर एक ग्रुप से शुरू हुई साफ-सफाई की इस मुहिम का ऐसा असर हुआ कि दो साल में इस अभियान से 25 हजार से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और राजधानी के इलाकों को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। दो वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से दक्षिणी निगम के एक अभियंता इस कदर प्रेरित हुए कि उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू उठाकर गंदगी के खिलाफ जंग छेड़ दी। सफाई की इस लड़ाई में उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाते हुए फेसबुक पर 'माई दिल्ली कीप इट क्लीन' नाम से एक ग्रुप बनाया। दोस्तों संग शुरू हुए ग्रुप के काम और स्वच्छता के इस अभियान में देखते ही देखते 25 हजार से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ग्रुप सदस्य हर रविवार किसी भी गंदगी वाले इलाके की सफाई के लिए निकल पड़ते हैं। ग्रुप में अधिकांश नौकरीपेशा लोग जुड़े हैं जो अपने शहर को स्वच्छ रखने में भागीदारी निभा रहे हैं।

धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ध्यान- राजीव जैन बताते हैं कि हमारे ग्रुप के सदस्य अपने घरों से बाल्टी, झाड़ू, वाइपर जैसे सामान लाते हैं और कहीं भी सफाई करने लग जाते हैं। हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास बड़ी गंदगी देखी जा सकती है। यमुना बाजार हनुमान मंदिर के प्रांगण में इस हद तक गंदगी और कीचड़ फैल चुका था कि उसे साफ करने के लिए हमनें कई बार लगातार अभियान चलाए। आज वहां आने वाले भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है।.

केंद्र सम्मानित कर चुका है- जैन के फेसबुक वर्चुअल ग्रुप 'माई दिल्ली कीप इट क्लीन' को बीते वर्ष 2 अक्तूबर को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से विशेष पुरस्कार दिया जा चुका है। ग्रुप को सेल्फ हेल्प श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली के मंदिरों, रेलवे स्टेशन, सड़क, चौराहों को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए गए स्वच्छता कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। कुछ दोस्तों के साथ शुरू हुआ ये ग्रुप आज स्वच्छताग्राहियों का बड़ा प्लेटफॉर्म है।

आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 300 लोगों को ठगा

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-16 स्थित जेजे कॉलोनी में स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के नाम पर शातिर ने 300 गरीब लोगों से ठगी कर ली। आरोपी ने योजना का लाभ दिलाने के लिए उनके फॉर्म भरने के बदले में 100-100 रुपये ठग लिए। ठगी का पता चलने पर बुधवार को लोगों ने पकड़कर आरोपी की धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आयुष्मान भारत योजना को महज तीन दिन हुए हैं। अभी सही से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इसी का चालबाज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को खोड़ा कॉलोनी का रहने वाला महेशचंद कार से सेक्टर-16 जेजे कॉलोनी पहुंचा। युवक ने लोगों को इस योजना के बारे बताया और रकम दिलाने का लालच देकर 100-100 रुपये में फॉर्म भरने शुरू कर दिए।

संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन

बुधवार को अपनी मांगों को लेकर संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन करते गाडिया लोहार संघर्ष समिति के सदस्य।

सौर ऊर्जा से अपने घर पर बिजली बनाएं और बेचें भी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार घरेलू क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सौर ऊर्जा से संबंधित नई नीति को मंजूरी दी गई। आप अपने घर को सोलर हाउस बना सकते हैं। यानि आप सौर ऊर्जा से बिजली बना भी सकते हैं और सरकार को बेच भी सकते हैं। इस नीति के तहत प्रति यूनिट 2 रुपये की दर से सरकार सब्सिडी देगी। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है।

ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ग्रुप हाऊंसग सोसायटी में भी सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी गई है। इसमें आम जनता को कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा।

दो रुपये प्रति यूनिट की दर से सरकार की तरफ से और करीब तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड) पैसा देगी। पहले साल में कम से कम 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जहां पर ज्यादा जगह उपलब्ध है, वहां पर उपभोक्ता सीधे ग्रिड को बिजली बेच सकेंगे। जो लोग व्यक्तिगत रूप से घर पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उन्हें भी 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से छूट मिलेगी।

नोएडा: ग्राइंडर की ब्लेड बदल रहा था युवक, तभी किसी ने चालू कर दी मशीन, हुई मौत

नई दिल्ली। नोएडा के एनएसइजेड स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार को एक युवक मशीन की चपेट में आ गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक (24) वाजिद मूलरूप से छपरा बिहार का रहने वाले थे और सलारपुर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि वाजिद उस दौरान मशीन की सफाई कर रहा था, तभी किसी ने मशीन को चालू कर दी और मशीन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सलारपुर कॉलोनी में किराये के मकान में रहने वाले वाजिद (25) की दस अगस्त को एनएसईजेड स्थित प्लास्टिक का दाना बनाने वाली एक फैक्टरी में मशीन ऑपरेटर की नौकरी लगी थी। बुधवार सुबह 9 बजे फैक्ट्री में पहुंचकर वाजिद ने मशीन को बंद करके उसकी साफ-सफाई शुरू की। वाजिद मशीन का ब्लेड बदल रहा था, तभी किसी कर्मचारी ने मशीन का स्विच ऑन कर दिया।

राज्यों को पिछड़ापन दिखाने के लिए आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं

st/sc प्रमोशन में रिजर्वेशन अब दे सकती हैं सरकारें

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है।

संविधान पीठ ने कहा है कि राज्यों को इन समुदायों में पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए संख्यात्मक आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को दिए गए फैसले ने एक बड़ी बाधा हो हटा दिया जिसका हवाला केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देते वक्त दिया था। यह मामला पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास पहुंचा था। उसने पदोन्नति में आरक्षण के बारे में नागराज मामले में 2006 का फैसला सात सदस्यों की पीठ को भेजने से इंकार कर दिया। नागराज मामले में 2006 में सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए शर्तें तय की थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एम नागराज मामले में उसके 12 साल पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नागराज मामले में अदालत ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और कुल मिलाकर प्रशासनिक दक्षता पर असर नहीं होने के बारे में संख्यात्मक आंकड़ा देने के लिए बाध्य हैं।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि नागराज मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए संख्यात्मक आंकड़े जुटाने की बात कहना इंदिरा साहनी मामले में 1992 में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है। इसलिए उसने नागराज मामले में दिए गए फैसले को उस हद तक अमान्य ठहरा दिया जिसमें आंकड़े जुटाना अनिवार्य कर दिया गया था। संविधान पीठ ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नागराज मामला सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए संख्यात्मक आंकड़े जुटाने को कहने वाला नागराज मामले का निष्कर्ष इंदिरा साहनी मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के खिलाफ है इसलिए उसे उस हद तक अमान्य ठहराया जाता है। संविधान पीठ में जस्टिस कुरियन जोसफ, रोहिंटन फली नरीमन, संजय किशन कौल और इंदु मल्होत्रा भी शामिल थीं।

एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दिए आधार समेत तीन बड़े फैसले

नई दिल्ली ■ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों के लिहाज से बुधवार का दिन बेहद खास है। सुबह कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक के बाद एक अबतक कुल तीन बड़े फैसले आ चुके हैं। प्रमोशन में आरक्षण के बाद आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च अदालत का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है, लकिन कुछ शर्तों और बदलावों के साथ. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर जगह आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति भी दे दी है। आइए एक-एक कर समझते हैं कि बुधवार को कौन-कौन से फैसले आए और इन ताबड़तोड़ फैसलों के मायने क्या हैं?

दूसरा फैसला: आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार

प्रमोशन पर आरक्षण के फैसले की खबर आए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से बहुचर्चित आधार मामले पर बड़ा फैसला आ गया। कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बनाना जरूरी नहीं है। कोई भी मोबाइल कंपनी आधार कार्ड की डिमांड नहीं कर सकती है। फैसला पढ़ते हुए जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि आधार कार्ड की ड्यूप्लिकेसी संभव नहीं है और इससे गरीबों को ताकत मिली है। फैसले में कहा गया, शिक्षा हमें अंगूठे से दस्तखत पर लाती है और तकनीक हमें अंगूठे के निशान पर ले जा रही है। आपको बता दें कि आधार पर देश में काफी समय से बहस चल रही थी। अब इस फैसले से आधार पर जारी सियासी दंगल भी थम जाएगा।

92 वर्षीय रिटायर्ड जज ने दी थी आधार को चुनौती लड़ी लंबी लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वाली पांच जजों की पीठ ने आधार पर अहम फैसला सुनाते हुए इसकी वैधता तो बरकरार रखी, लेकिन बैंकों, मोबाइल सिमों और स्कूलों में एडमिशन के लिए इसकी जरूरत को खत्म कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा हमें अंगूठे से बाहर लाई थी लेकिन आज की तकनीक फिर से हमें अगूंठे पर ले आई है। आधार के खिलाफ लड़ाई में कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस केएस पुट्टास्वामी का नाम भी आता है। जस्टिस केएस पुट्टास्वामी ने 2012 में आधार की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस समय मनमोहन सरकार थी। जस्टिस पुट्टास्वामी ने मनमोहन सरकार से लेकर मोदी सरकार तक अपनी लड़ाई जारी रखी। साल 2010 में जब मनमोहन सरकार ने आधार को लॉन्च किया और विभिन्न सरकारी सेवाओं से इसे जोड़ने की मुहीम शुरू की तो जस्टिस पुट्टास्वामी इसका विरोध किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब जस्टिस पुट्टास्वामी 86 साल के थे और अब उनकी उम्र लगभग 92 साल हो गई है। जस्टिस पुट्टास्वामी की याचिका के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

प्रमोशन में आरक्षण: गेंद राज्यों के पाले में

सुबह 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट से पहला फैसला प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आया। शीर्ष अदालत ने सीधे तौर पर प्रमोशन में आरक्षण को खारिज न करते हुए इसे राज्यों पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह अर्जी खारिज कर दी कि एससी-एसटी को आरक्षण दिए जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए। इस पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। यूपी की पूर्व सीएम ने कहा है कि फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ऐसे में सरकारें प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। माना जा रहा है कि इस पर सियासत शुरू हो सकती है।

तीसरा फैसला: कोर्ट की सुनवाई लाइव

अब तक हम कोर्ट के फैसलों को पढ़कर ही जानते आए हैं पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों की सुनवाई हम लाइव देख सकेंगे। इस बाबत बुधवार दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा बड़ा फैसला दिया। सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग से अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और यह जनहित में होगा। आपको बता दें कि समय-समय पर समाज के भीतर से ऐसी मांग उठती रही है कि कोर्ट की कार्यवाही को लाइव किया जाए, जिससे जनता को पता चल सके कि वकील किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं। इसके लिए पश्चिमी देशों का भी हवाला दिया था।

आधार पर फैसले को वित्त मंत्री ने बताया ऐतिहासिक

सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता व अनिवार्यता पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया, जिसमें कुछ शर्तों के साथ आधार अनिवार्य कर दिया गया। वित्त मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद एक देश और एक पहचान को कानूनी मान्यता मिल गई है।

सरकार ने बचाए 90 हजार करोड़- सरकार ने आधार की वजह से प्रतिवर्ष 90 हजार करोड़ बचाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम आधार के तमाम बिंदुओं पर फैसला दिया है। लेकिन आधार की संवैधानिकता को लेकर जो सवाल उठाए जाते रहे हैं अब उस पर विराम लग जाएगा।

जेटली ने कांग्रेस पर कसा तंज- जेटली ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले से चिंतित है। कांग्रेस जरूर इस आइडिया को लाई लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है।

यहां जरूरी है आधार

- सुरक्षा मामले में आधार मांग सकती हैं एजेंसियां
- आयकर दाखिल करने और पैन के लिए आधार जरूरी
- सरकार की लाभकारी योजना और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी
- पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा आधार कार्ड

यहां जरूरी नहीं है आधार

- बैंक में खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं
- नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार जरूरी नहीं
- यूजीसी, सीबीएसई आधार को जरूरी नहीं कर सकते
- 6 से 14 साल के बच्चे के दाखिले में आधार जरूरी नहीं
- निजी कंपनियां नहीं कर सकतीं आधार कार्ड की मांग

अयोध्या मामले से जुड़े केस में अहम फैसला आज

अयोध्या मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। अयोध्या का राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अयोध्या की जमीन किसकी है, इस पर अभी सुनवाई की जानी है। बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारुकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और ऐसे में इस फैसले को दोबारा परीक्षण की जरूरत है और इसी कारण पहले मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि कोर्ट इस पहलू पर फैसला लेगी कि क्या 1994 के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को दोबारा देखने के लिए संवैधानिक बेंच भेजा जाए या नहीं।

प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई

सभी जोन के पांच-पांच बाजारों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य

एजेंसी, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने मार्केट में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों पर वौंक कसना शुरू कर दिया है। निगम ने इसके लिए छापेमार टीम का गठन किया है, जो दुकान-दुकान जाकर प्लास्टिक की थैलियों को जब्त कर जुर्माना लगाएगी। इससे पहले निगम ने दुकानदारों को जागरूक करने का काम भी शुरू कर दिया है और पहले चरण में सभी जोन में कम से कम पांच-पांच मार्केट प्लास्टिक से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। नगर निगम सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने में स्कूली बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। निगम के अधिकारी आए दिन अलग-अलग इलाकों में स्कूली बच्चों को लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। बुधवार को बच्चों ने अलग-अलग जोन के मार्केट में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर पर्चे बांटे और प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से भी आगाह किया। अभियान के तहत बड़ी तादाद में बाजारों से प्लास्टिक की थैलियां बरामद की जा रही है। शायद यही वजह है कि निगम के डर से कुछ दुकानदारों ने कागज की थैलियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। निगम के एक अधिकारी ने बुधवार को हर जोन के कम से कम पांच-पांच बाजारों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने की बात कही। सफाई अभियान के साथ ही नगर निगम ने नजफगढ़ जोन के ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों के आसपास सफाई अभियान चलाया। बुधवार को नगंली, सकरावती और पोचनपुर के तालाबों के आसपास अभियान चला। इस अभियान में क्षेत्रीय पार्षदों, आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पश्चिमी जोन में शौचालयों की सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम ने जनकपुरी स्थित महिला शौचालय में सेनेट्री नेपकिन की बेंडिंग मशीन की शुरुआत भी की। दक्षिणी जोन के ग्रीन पार्क, पुष्प विहार, मध्य जोन के अबुल फजल एंकलेब व आसपास पाकरे एवं बस स्टॉपों की सफाई भी की गई।

धारा 497 : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर दिल्ली महिला आयोग असहमत

नई दिल्ली। व्यभिचार को गैर आपराधिक घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने असहमति और दुख जताया है। उन्होंने गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में इस फैसले पर पुनर्विचार करने की वकालत की है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि व्यभिचार को गैर आपराधिक घोषित करके उच्चतम न्यायालय ने इस देश के लोगों को शादी से बाहर अवैध सम्बन्ध रखने की खुली छूट दे दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय को अवैध संबंधों को बिना लिंगभेद के महिला और पुरुष दोनों के लिए आपराधिक करना चाहिए था। इसकी जगह उन्होंने व्यभिचार को ही गैर आपराधिक घोषित कर दिया। शादी के बाहर संबंध अब अपराध नहीं, आयोग के समक्ष महिलाओं की ऐसी हजारों शिकायतें आती हैं जिनमें उनके पतियों के शादी से बाहर अवैध सम्बन्ध हैं। यही नहीं उन्होंने अपनी पत्नियों तक को छोड़ दिया है। ये महिलाएं अपने पति के सहारे के बिना खुद का और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अकेली छोड़ दी जाती हैं।

प्रतियोगिता हमें अधिक सक्षम बनाती हैं, नये जवाब तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं और इस दंभ से बचाती हैं कि हम सब कुछ जानते हैं -टाम मोनाहन

आरक्षण का रास्ता

न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण का रास्ता फिर से साफ करना अपेक्षित था। इससे पहले जून में भी इस पर अंतरिम फैसला देते हुए न्यायालय ने कहा था कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक प्रोन्नति में आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ओर से स्पष्ट फैसला देने की जगह इसे राज्यों पर छोड़ दिया है। यानी राज्य सरकार चाहें तो प्रोन्नति में आरक्षण दे सकती है। वस्तुत: शीर्ष न्यायालय ने 2006 के नागराज मामले के अपने फैसले में जो दो शत्रे लगाई थीं, उनका विरोध आरक्षण समर्थकों एवं सरकार ने किया था। इनमें एक तो यह था कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के पहले यह देखा जाए कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं और दूसरा प्रशासनिक दक्षता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं करने से जुड़ा था। सामान्य शब्दों में कहें तो सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण तभी दे सकती है, जब आंकड़ों के आधार पर तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है और वह प्रशासन की मजबूती के लिए जरूरी है। हालांकि राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 16-4ए और अनुच्छेद 16-4बी के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के प्राप्त अधिकार को तब भी समाप्त नहीं किया था किंतु इन दो शतरे के कारण इसको अमल में लाने में कठिनाई आ रही थी। इसके खिलाफही न्यायालय में याचिकाएं डालीं गई थीं। न्यायालय ने बस इतना किया है कि उन शतरे को हटा दिया है। तो अब स्थिति पूर्ववत है। प्रोन्नति में आरक्षण पर हमेशा से दो राय रही है। जिसे आरक्षण के तहत नौकरी मिल गई उसे प्रोन्नति उसके कार्यप्रदर्शन के आधार पर दिया जाए। दूसरी राय यह है कि उन जातियों को अपने मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वैसी सुविधाएं और वातावरण नहीं मिलते जैसे दूसरी जातियों को मिल जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बहस बंद हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है कि इससे परिश्रम और दक्षता से काम करने वाले सामान्य वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के मनोविज्ञान पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह चलता रहेगा। जब संपूर्ण आरक्षण पर ही आज तक देश में सहमति नहीं है तो प्रोन्नति के संदर्भ में ऐसा कहां से हो सकता है?

लाभकारी योजनाओं और सज़्सिडी

आधार नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद इस पर जारी विवाद बंद हो जाना चाहिए। न्यायालय ने साफ विभाजन रेखा खींच दिया है कि कहां आधार नंबर देना जरूरी है और कहां नहीं। जाहिर है, इससे संबंधित भ्रम साफ हो गया है। आयकर रिटर्न भरने, पैन कार्ड बनवाने एवं सरकारी लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी प्राप्त करने के अलावा कहीं भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। यही नहीं बैंको, मोबाइल कंपनियों या ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा आधार नंबर मांगना अब अवैध होगा। न्यायायल द्वारा आधार कानून की धारा 57 को रद्द कर देने के साथ ही निजी कंपनियों के आधार नंबर मांगने के अधिकार समाप्त हो गए हैं। सच है कि आधार नंबर का जैसा अतिवादी प्रयोग होने लगा था, उससे लोगों को परेशानी हो रही थी और खीझ भी पैदा होती थी। अगर बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसे जरूरी सेवाओं से वंचित कर देंगे यह कहां का न्याय है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जनिहत को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला दिया है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इसने याचिकाकर्ताओं की यह दलील भी मान ली है कि आधार कार्ड निजता का अतिक्रमण है और यह संविधान में मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। पीठ द्वारा बहुमत से इसकी संवैधानिकता की स्वीकृति सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। न्यायालय ने यह कहकर सरकार का पक्ष मजबूत भी किया है कि आधार आम लोगों के हित के लिए काम करता है और इससे समाज में हाशिये पर बैठे लोगों को फायदा होगा। साफ है कि शीर्ष अदालत संवैधानिकता के मामले में सरकार के साथ है तो सुरक्षा मामले में यूएआईडीआई के प्रमाणों को सही मानता है। लेकिन सरकार पर यह बंधन लग गया है कि वह बिना न्यायालय की इजाजत के बायॉमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी और एजेंसी से शेयर नहीं कर सकती। कई बार इससे सरकार को परेशानी आएगी क्योंकि किसी पर कोई मामला दर्ज हो तो जांच एजेंसियों को उसका बयोमेट्रिक डेटा चाहिए होगा। न्यायालय का आदेश मिलने में देर होने पर जांच में बाधा आ सकती है। बावजूद इसके इसे डेटा सुरक्षा सुनिश्चित रखने के पूर्वोपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए।

सत्संग

परमात्मा

खाया हुआ सांप आक्रमणकारी पर ऐसी फूफकार मारकर दौड़ता है कि उसके होश छूट जाते हैं, बचाव के लिए भागना ही पड़ता है। सांसारिक व्यथाओं से विक्षुब्ध मनुष्य की भी ऐसी ही स्थिति होती है। जब मनुष्य को पीड़ाएं चारों ओर से घेर लेती हैं और कोई सहारा नहीं सूझता तो वह निष्ठापूर्वक अपने परमेश्वर को पुकारता है। हार खाये हुए मनुष्य की कातर पुकार से परमात्मा का आसन हिल जाता है और उन्हें सारी व्यवस्था छोड़कर भक्त की सेवा के लिए भागना पड़ता है। मनुष्य ने बुलाया हो और उसकी शुभेच्छा न आई हो, मनुष्य ने सहायता मांगी हो और परमात्मा ने मनोरथ पूर्ण न किया हो, मनुष्य की प्रार्थना पर परमात्मा दौड़ कर न चला आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे बुलाइये, वह आपके अंत:करण में दिव्य प्रकाश बनकर उतरेगा, मधुर संगीत बनकर हृदय में गुंजन करेगा, आशीर्वाद बनकर आपके दु:ख दर्द दूर करेगा। पर उसे सच्चे हृदय से बुलाइये, निष्कपट और निश्चल होकर पुकारिये। ऐसा समय आता है जब मनुष्य संसार को भूलकर कुछ क्षण के लिए ऐसे दिव्य लोक में पहुंचता है, जहां उसे असीम सहानुभूति और शाश्वत शांति मिलती है। प्रार्थना की इस आंतरिक स्थिति और उसके आनंद को कोई भुक्त भोगी ही जान सकता है। परमात्मा के निकट पहुंच कर आत्मा जब भक्ति भावना से अपनी संवेदनाएं प्रस्तुत करती है, तो अनिर्वचनीय आनंद मिलता है। अंत:करण की समस्त वासनाएं विलीन हो जाती हैं, इंद्रियों की चेष्टाएं शांत हो जाती हैं। हिरण्यकश्यपु की हठधर्मिता से दुखी बालक प्रह्लाद ने उसे बार-बार पुकारा, उसका नारायण बार-बार उसकी मदद के लिए दौड़ा। विष पिया उसके भगवान ने समुद्र के गर्त में पाथेय बना प्राद का भगवान। इससे भी काम न चला तो नृसिंह बनकर प्रह्लाद का भगवान खंभा चीरकर दौड़ा आया। जिसने मनुष्य को पैदा किया उसके हृदय में अपनी संतान के लिए मोह न हो? ममता न हो यह कैसे हो सकता है? मनुष्य बुलावे और वह न आए ऐसा कभी हुआ नहीं। द्रौपदी जान गई थी कि सभा में उसे बचाने वाला कोई नहीं है। दु:शासन चीर खींचता है। लाज न चली जाए, इस भय से निर्बल नारी दीनानाथ को पुकारती है। भगवान श्रीकृष्ण आते हैं और उसका चीर को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। दु:शासन थककर चूर हो गया, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। परमात्मा की लीला अपरंपार है।

''छोटे दिमाग के लोग बड़ी-बड़ी कुर्सियों

प्रधानमंत्री जनता के इस गुस्से की उपेक्षा कैसे कर सकते थे लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि क्या भारत-पाक संबंधों को हम किसी एक सिरफिरे पाकिस्तानी फौजी या आतंकवादी के हाथों गिरवी रख सकते हैं? वह बर्बरतापूर्ण कृत्य सर्वथा निंदनीय है लेकिन क्या वह इमरान खान के इशारे पर किया गया था? इसके अलावा यह हत्या तो भेंट की घोषणा के दो दिन पहले याने 18 सितम्बर को हुई थी। तो फिर 20 सितम्बर को भारत सरकार ने भेंट की घोषणा क्यों की? क्या हमारे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है? क्या हमारे नेता और अफसर इतनी नाजुक खबरों से भी बेखबर रहते हैं? दो दिन बाद की गई भेंट की घोषणा से यह भी सिद्ध होता है कि नरेंद्र सिंह की नृशंस हत्या पर भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था।

सतीश पेडणोकर

विदेश मंत्रियों की न्यूयार्क में होनेवाली भेंट का रद्द होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा यह हुआ कि दोनों देशों की तरफ से एक-दूसरे के नेताओं के लिए बेहद अमर्यादित बयान जारी हुए। इस भेंट को रद्द करने की घोषणा करते हुए भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि अब ''इमरान खान का असली चेहरा उजागर हो गया' और उनके ''कुत्सित इरादे' भी! इतना सुनते ही इमरान ने ईट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने मोदी का नाम लिये बिना कहा कि ''छोटे दिमाग के लोग बड़ी-बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं।' वे अहंकारी और निषेधात्मक हैं। सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी की भेंट को रद्द भारत ने किया। उसे रद्द करने के तीन कारण भारत ने गिनाए। पहला, एक भारतीय जवान नरेंद्र सिंह की पाकिस्तानी सेना द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या। दूसरा, कश्मीर के तीन पुलिसवालों का उनके घर से अपहरण और उनकी हत्या। तीसरा, बुरहान वानी समेत 20 आतंकवादियों की स्मृति में पाकिस्तान सरकार द्वारा डाक टिकट जारी करना। ये तीनों कारण ऐसे नहीं हैं, जिनके कारण उक्त भेंट रद्द की जानी चाहिए थी। इसमें शक नहीं कि हमारे जवान के सिर काटे जाने की घटना ने भारत में काफी गुस्सा पैदा कर दिया था। प्रधानमंत्री जनता के इस गुस्से की उपेक्षा कैसे कर सकते थे लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि क्या भारत-पाक संबंधों को हम किसी एक सिरफिरे पाकिस्तानी फौजी या आतंकवादी के हाथों गिरवी रख सकते हैं? वह बर्बरतापूर्ण कृत्य सर्वथा निंदनीय है लेकिन क्या वह इमरान खान के इशारे पर किया गया था? इसके अलावा यह हत्या तो भेंट की घोषणा के दो दिन पहले याने 18 सितम्बर को हुई थी। तो फिर 20 सितम्बर को भारत सरकार ने भेंट की घोषणा क्यों की? क्या हमारे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है? क्या हमारे नेता और अफसर इतनी नाजुक खबरों से भी बेखबर रहते हैं? दो दिन बाद की गई भेंट की घोषणा से यह भी सिद्ध होता है कि नरेंद्र सिंह की नृशंस हत्या पर भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था।

विदेश मंत्रियों की भेंट अचानक पहले रद्द की और बाद में इस हत्या को बहाना बना दिया। इस तरह हमारी सरकार ने एक खोखला कारण और भी खोज निकाला। वह यह कि इमरान की सरकार ने आतंकवादियों की स्मृति में डाक टिकट जारी किए। इमरान ने शपथ ली 25 जुलाई को और ये डाक टिकट जारी हुए करीब दो हफ्ते पहले। इसमें इमरान का क्या दोष? यदि हमारी सरकार को कोई बहाना बनाना था तो उसे पहले तारीखें चेक कर लेनी थीं। जिन अफसरों ने ये रद्दी कारण बताकर इतनी महत्त्वपूर्ण भेंट भंग करवा दी, उनको कुछ नसीहत जरूर दी जानी चाहिए। यहां एक बुनियादी सवाल यह भी उठता है कि इस सरकार को कौन चला रहे हैं? नेता या अफसर? जो तीसरा कारण बताया गया है, भेंट के रद्द होने का, वह भी संदेह के घेरे में है। कश्मीर के आतंकवादी आए दिन ऐसे कारनामे करते रहते हैं, जो वहशीपन से कम नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की शै भी रहती है। हो सकता है कि यह मामला भी पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया हो लेकिन उसके ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं। मान लें कि पाक फौज ने ही यह करवाया है, तो भी इसके बहाने भेंट को भंग करवाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। पाक फौज ऐसे जघन्य कृत्य अक्सर करवाती ही रहती है। यह जो कृत्य था, इसमें नया क्या था? अजूबा क्या था? यह भी हो सकता है कि कश्मीर या पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने जान-बूझकर इस वक्त यह करतूत की हो ताकि भारत-पाक संवाद के पहले ग्रास में ही मक्खी पड़ जाए। मक्खी तो पड़ गई। यानी हमारी सरकार आतंकवादियों की चाल का मोहरा बन गई। यदि सरकार में दूरदृष्टि और गंभीरता होती तो इन तीनों मुद्दों को वह न्यूयार्क की भेंट में जमकर उठातीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शब्दों की मलिका हैं। वह कुरैशी की बोलती बंद कर देतीं। कुरैशी उनसे जरूर प्रभावित होते और यह भेंट दोनों राष्ट्रों के सार्थक संवाद में बदल जाती लेकिन हमारे प्रवक्ता ने चतुराई भरी कूटनीति करने की बजाय लट्ठमार राजनीति कर डाली। उसने नाम लिये बिना इमरान खान को फौज का मोहरा बता दिया और उन्हें ''तालिबान खान' सिद्ध कर दिया।

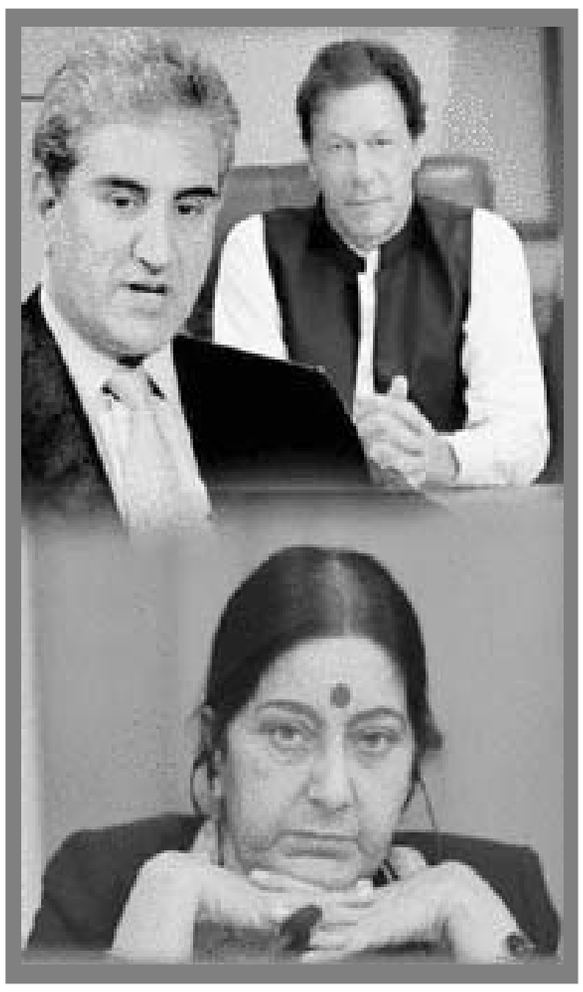

इमरान और फौज के संबंधों के बारे में किसे पता नहीं है मगर ये ही संबंध ऐसा रूप भी धारण कर सकते हैं, जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की है। यानी नेता आगे-आगे और फौज उसके पीछे-पीछे! इसका उल्टा होता ही रहता है लेकिन हमारी सरकार ने इमरान के आने पर जो नया मौका उसके हाथ लगा था, उसे गवां दिया है। इसका मूल कारण शायद यह है कि हमारी विदेश नीति का संचालन ठीक-ठाक नहीं है। भारत-पाक संवाद को पहले भी सिर्फ इसीलिए भंग कर दिया गया था कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त से हुर्रियत के नेता मिल लिये थे। हुर्रियत के नेता पहले भी पाकिस्तानी दूतावास से सतत संपर्क में रहते थे और उनसे प्रधानमंत्री नरसिंह राव और अटलजी की बात भी चलती रहती थी। इमरान खान ने भेंट के भंग होने पर मोदी के लिए जो बात कही, वह वैसी ही है, जैसी मोदी के बारे में राहुल गांधी की होती है या राहुल के बारे में भाजपाइयों की होती है। घरेलू राजनीति में किसी पर कोई लगाम नहीं रहती, परंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक-एक शब्द संभलकर बोलना होता है। मियां नवाज ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना गंवारु औरत से कर दी थी किंतु इमरान ने मोदी के बारे में जो कहा है, क्या वह उन पर भी लागू नहीं होता? बड़ी-बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले कितने लोग सचमुच बड़े होते हैं? कुर्सियों से उतरने के बाद ज्यादातर राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की कीमत उन कुर्सियों के बराबर भी नहीं रहती। इमरान के बोल ने इतने तीखे घाव कर दिए हैं कि उनकी दुर्गंध अब संयुक्त राष्ट्र महासभा को परेशान करेगी। कुरैशी कश्मीर की बीन बजाएंगे और सुषमा आतंकवाद का ढोल पीटेंगी। पता नहीं हमारे अगले चुनाव तक अब भारत-पाक संवाद पटरी पर आएगा या नहीं। चुनाव की इस बेला में यदि पाकिस्तान-विरोधी माहौल भारत में बना रहे तो यह मोदी के लिए मददगार ही होगा। इमरान के आने पर जो नई किरण फूटी थी, वह अभी बुझ-सी गई है।

चलते चलते

बारिश से असलियत

दिल्ली की समस्या बारिश से नदियां बनती सड़कें नहीं हैं, कचरे से बंद पड़े नाले-नालियां नहीं हैं, कूड़े के ढेर नहीं हैं, बल्कि बिगड़ी हुई आबो हवा ही है। महंगाई और बेरोजगारी वगैरह तो लगता है अब इस मुल्क की ही समस्या नहीं रही तो दिल्ली की समस्या वे क्या बनेंगी? बारिश ने केरल को तो चाहे कीचड़ से भर दिया हो।

दिल्ली की आबो-हवा साफ हो गई। आजकल दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या हर रोज होते बलात्कार, हर रोज होती हत्याएं और दूसरे अपराध नहीं हैं, बल्कि लगता है बिगड़ी आबो हवा ही है। दिल्ली की समस्या बारिश से नदियां बनती सड़कें नहीं हैं, कचरे से बंद पड़े नाले-नालियां नहीं हैं, कूड़े के ढेर नहीं हैं, बल्कि बिगड़ी हुई आबो हवा ही है। महंगाई और बेरोजगारी वगैरह तो लगता है अब इस मुल्क की ही समस्या नहीं रही तो दिल्ली की समस्या वे क्या बनेंगी ?बारिश ने केरल को तो चाहे कीचड़ से भर दिया हो। बारिश ने साफ-सुंदर इंदौर शहर में तो चाहे कीचड़ फैला दिया हो, पर दिल्ली की आबो हवा उसने जरूर साफकर दी। उसने स्वच्छता अभियान को भी मात दे दी। दिल्ली में बारिश से ट्रैफिक जाम तो चाहे कितना ही होता हो और उससे प्रदूषण भी चाहे कितना ही फैलता हो, पर उसने दिल्ली की आबो हवा साफ कर दी। वैसे तो कुछ लोगों का मानना है कि यह जो बारिश है, वह अब बेमौसम बारिश की तरह ही हो रही है। पर वह भी आबो हवा में आए बदलाव से ही है, फिर भी उसने दिल्ली की आबो हवा को साफ कर दिया। इसके बाद भी भविष्य की धुंध तो साफ नजर आ रही है। नहीं जी, हरियाणा और पंजाब में जलाई जानेवाली पराली से होने वाली धुंध की बात नहीं हो रही। यह धुंध तो तेल की बढ़ती कीमतों से बढ़ती नजर आ रही है। लोग आशंकाओं से भरे हुए हैं कि तेल की कीमतें लगता है शतक मारेंगी। यह जो भविष्य की धुंध नजर आ रही है, यह तो रुपये की गिरती हुई कीमत से पैदा होती जा रही धुंध है। लोगों को इस गिरावट में भी शतक की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यह बढ़ते अपराधों ने जो सामाजिक रिश्तों को एकदम ही धुंधला कर दिया है, यह धुंध कब छटेगी? अब विपक्षी एकता का तो जो होगा, सो होगा, पर यह भीड़ हिंसा की धुंध कब छटेगी? बच्चों की शिक्षा का भविष्य पूरी तरह धुंधला नजर आ रहा है, यह बदलते पाठक्रमों की धुंध, यह शिक्षण संस्थानों में हिंसा की धुंध यह कब छटेगी? अगर थोड़ी सी राजनीतिक आबो हवा भी साफ हो जाए तो कुछ बात बने। अगर कुछ सामाजिक आबो हवा भी साफहो जाए तो कुछ बात बने।

फोटोग्राफी...

पटना के निकट दानापुर में बुधवार को एक आर्मी रिक्रूटमेंट केंद्र में शारीरिक परीक्षण से गुजरते अभ्यर्थी।

आबादी वाला देश

युक्त राट्र संघ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2050 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होगा यानी चीन को भी भारत आबादी के मामले में पछाड़ देगा। यदि आबादी की रफ्तार और भी तेज हुई तो 2050 के पहले ही भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। जो आंकड़े बढ़ती आबादी के राज्यवर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, उससे यह साबित होता है कि देश के बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों ने आबादी की रफ्तार पर काबू पाने में अधिक सफलता पाई है। ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र, हिमाचल, गोवा, पंजाब, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर। बढ़ती आबादी के साथ घटते संसाधन और इसी के साथ बढ़ती बेरोजगारी देश में कई आसन्न समस्याओं को जन्म देते दिखाई दे रहे हैं, जो विकास की राह में बहुत बड़े रोड़े साबित हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम परिवार नियोजन की योजनाओं, अभियानों और कार्यक्रमों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सशक्त भूमिका के बावजूद भारत में जनसंख्या की समस्या लगातार बढ़ती रही है। मौजूदा भारत की आबादी 1.25 एक सौ पच्चीस करोड़ से अधिक हो गई है। संयुक्त राट्रसंघ के मुताबिक 2025 तक यह चीन की आबादी को भी पीछे छोड़ देगा। इस वक्त भारत की आबादी 1.45 एक अरब पच्चीस करोड़ के करीब होगी। आबादी बढ़ने की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन जन्म दर की अपेक्षा मृत्युदर कम होने के कारण महज 2001 से 2010 के दौरान 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले पांच सालों में लगभग औसत जनसंख्या बढ़ने का यही हाल रहा है। यह वृद्धि पिछली जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना में 17.64 प्रतिशत अधिक है। अब भी भारत की जनसंख्या 1.4 प्रतिषत वार्षिक दर से बढ़ रही है जो कि चीन के 0.6 से ढाई गुना अधिक है। विषेशज्ञों के मुताबिक पानी, जमीन, खादान्न, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक संसाधनों में लगातार कमी आती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पीने वाले पानी और शुद्ध खाद्यान्न की है। देश के अभी हजारों गांवों में जरूरत के अनुसार शिक्षा, स्वास्य, रोजगार और पीने लायक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे गांवों से लगातार पलायन हो रहा है और शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक यदि गांवों से शहरों की ओर होता पलायन नहीं रुका तो 2030 तक शहरों की आबादी बढ़कर 40 फीसद से ज्यादा हो जाएगी। इससे शहरों में जनसंख्या का भार और बढ़ेगा जिससे नई-नई समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कैसे लोगों को बेहतर स्वास्य, मकान, कपड़ा, शुद्ध पीने का पानी और खाना, साथ ही अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए। गरीब आदमी छोटे परिवार की जगह बड़ा परिवार बनाने को प्राथमिकता देता है। बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधन का दोहन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की गहराती समस्या का एक बड़ा कारण यह भी है। भारत में बढ़ती आबादी की समस्या इसका स्थिरीकरण न होना है। स्थिरीकरण का मतलब, साल भर में जन्म लेने वाले वालों की संख्या तकरीबन उतनी ही होगी जितने लोगों की मौत होती है। वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक यदि टीएफआर दर 2020 में 2.1 फीसद आ जाती है तो उसके 35 साल बाद 2055 में आबादी का स्थिरीकरण हो पाएगा। जिसकी सम्भावना बहुत कम है। तमाम कवायदों के बावजूद लोगों में छोटे परिवार रखने के प्रति वैसी ललक नहीं बन पाई है जैसी आबादी के स्थिरीकरण के लिए जरूरी है। सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं निकालनी चाहिए, जिससे खेती और बागवानी पर मानव श्रम-शक्ति के कारण उस पर असर न पड़े और लोगों को परिवार नियोजन कराने के बाद परेशानी पैदा न हो।

न्यूज

चुनाव आयोग ने आप की खारिज की याचिका

नई दिल्ली ,(एजेंसी)। चुनाव आयोग ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विधायकों ने सरकारी अधिकारियों के क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत मांगी थी। अब इस मामले में अंतिम सुनवाई में 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले आयोग ने इस मामले में आप के 20 विधायकों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें इनकी ओर से याचिकाकर्ता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। आप विधायकों ने केस में सरकार का पक्ष रखने वाले गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग ने कहा कि जिरह की कोई जरूरत नहीं है। संसदीय सचिव नियुक्त आप के 20 विधायकों को लाभ का पद हासिल होने के बाद विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली प्रशांत पटेल की याचिका पर चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है।

मुख्यमंत्री रियो, गडकरी ने की समीक्षा बैठक

कोहिमा ,(एजेंसी)। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़क परियोजनाओं के संबंध में यहां एक समीक्षा बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि शिलांग स्थित स्टेट कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को श्री गड़करी के साथ हुई बैठक में श्री रियो ने नगालैंड चेक द्वार से बर्मा कैम्प राष्ट्रीय राजमार्ग 29 तक आरओबी समेत दो लेन सड़क के निर्माण के प्रस्ताव पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 129 और 29 दीमापुर शहर से होकर गुजरता है जो कि नागालैंड का सबसे बड़ा 'कामर्शियल हब 'है और पड़ोसी राज्य असम के कारबी आंगलोंग एवं गोलाघाट जिलों को जोड़ता है। शहर की व्यस्ततम यातायात के मद्देनजर इस मार्ग को दो लेन के रूप में विकसित किये जाने की जरूरत है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने शीघ्र मिलेगा लाइसेंस

मास्को ,(एजेंसी)। रूसी सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम और इसके साझेदारों को फिनलैंड में अगले वर्ष हनहिकिवी-1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए जल्द ही लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव की 26 सितंबर को फिनलैंड की यात्रा के मद्देनजर कहा जा रहा है कि हनहिकिवी-1 एनपीपी स्थापित करने की परियोजना अब लाइसेंस प्राप्त करने के चरण में है।2018 में लाइसेंस प्राप्त करने की उम्मीद है, हालांकि उसके फिनलैंड के सहयोगियों ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस 2019 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।

कृपानाथ मल्लाह असम विस के नए उपाध्यक्ष

गुवाहाटी,(एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृपानाथ मल्लाह को बुधवार को सर्वसम्मति से असम विधानसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्री मल्लाह रताबरी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हितेन्द्र नाथ गोस्वामी ने सदन में उनके (श्री मल्लाह) उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। श्री गोस्वामी, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, सभी विधायी दल के नेता और अन्य विधायकों ने श्री मल्लाह को बधाई दी। श्री मल्लाह ने अपने सहयोगियों को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया।

बांग्लादेश में विमान की आपात लैंडिंग

ढाका ,(एजेंसी)। बंगलादेश से अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले एक विमान को बुधवार को चटगांव में शाह अमानत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। शाह अमानत हवाई अड्डे के प्रबंधक सरवार ई जॉन ने 'दि डेली स्टार 'को बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण उड़ान संख्या बी एस 141 को अपरान्न करीब 13 बजकर 45 मिनट पर आपात स्थिति में उतारा गया। विमान पर चालक दल के सदस्यों समेत 171 यात्री सवार थे। विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। श्री जॉन ने कहा कि विमान ने साढ़े 11 बजे ढाका हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

बिहार : गरजती है एके-47, अपराधियों के बीच बनी स्टेटस सिंबल

पटना ■ एजेंसी

बिहार सरकार राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर ले लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के अपराधियों के हाथ में अब एके-47 की पहुंच हो गई है। हाल ही में मुंगेर जिले से कई एके-47 की बरामदगी, तस्करों की गिरफ्तारी और उनके बयानों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बिहार में अपराधियों के पास अब देसी कट्टे और बंदूकों को जगह एके-47 ने ले ली है। मुजफ्फरपुर में पूर्व महापौर समीर कुमार सिंह और उनके चालक की रविवार को अज्ञात अपराधियों ने सरेराह हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में पता चला कि अपराधियों ने समीर की गोलीबारी में पूर्व महापौर को 16 गोलियां लगीं, जबकि उनके चालक को 12 गोलियां। मुजफ्फरपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर भी मानती हैं कि इस घटना में एके-47 का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में यह तय है कि अब आम अपराधियों तक भी एके-47 पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, 'मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर को दिन-दहाड़े एके-47 से मार दिया गया। नीतीशजी की नाकामियों से बिहार में एके-47 आम हथियार हो गया है। ' तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में बिहार में एके-47 से हुई तीन हत्या की घटनाओं की भी जिक्र करते हुए लिखा, 'समस्तीपुर में बिजनेसमैन की हत्या, पटना में व्यवसायी की हत्या और मोतिहारी में छात्र की हत्या एके-47 से कर दी गई।' ऐसे में सवाल है कि आखिर मुंगेर और आम अपराधियों तक एके-47 पहुंची कैसे।

नीतीश की नाकामियों से बिहार में एके-47 आम हथियार हुआ

एमपी की ऑर्डिनेंस फैक्टरी से गायब हुई एके-47

पुलिस अधीक्षक बाबू राम कहते हैं कि जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्टरी से पिछले कुछ सालों में 50 से ज्यादा एके-47 गायब हुई थीं, इनमें अधिकांश हथियार बिहार पहुंचाए गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 29 अगस्त को मुंगेर के जमालपुर से इमरान को गिरफ्तार किया था। इमरान से हुई पूछताछ में यह पता चला था कि उसके पास जबलपुर के एक आदमी ने जमालपुर आकर तीन एके 47 उपलब्ध कराए थे। इसके बाद तस्कर श्मसेर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद 15 दिनों के अंदर मुंगेर के विभिन्न क्षेत्रों से आठ एके-47 बरामद की गई और अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं।

मेरठ में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पीड़ित लड़की बोली

पुलिस ने बनाया मुस्लिम लड़के पर एफआईआर का दबाव

घटना बीते रविवार की है, जब एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्रा एक घर के अंदर मौजूद थे। लड़की का कहना है कि वो दोनों वहां पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने भी लड़की से अभद्रता की और उस पर लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दबाव बनाया।

नई दिल्ली ■ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मेरठ से पुलिस की गुंडागर्दी का जो वीडियो सामने आया है, उसने योगी सरकार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुस्लिम लड़के से ताल्लुक होने पर पुलिस जवानों ने हिंदू धर्म की छात्रा के साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि उस पर अपने सहपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का दबाव भी बनाया। इस मामले में पीड़िता ने बातचीत में यूपी पुलिस पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ पढ़ने के लिए उसके घर पर गई थी, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर तांडव मचाया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस हम दोनों को अपने साथ ले गई। पीड़िता ने बताया कि पुलिस मुझे और मेरे दोस्त को अलग-अलग गाड़ी में लेकर गई। मैं जिस गाड़ी में थी, उसमें मौजूद पुलिसवालों ने मेरे साथ बदतमीजी की। मुझ पर मुस्लिम लड़के से रिश्ते होने का आरोप लगाया। मेरा नकाब उतरवाया गया और गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मी ने मेरा वीडियो बनाया और मेरे खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया।

लड़के के खिलाफ केस करने का दबाव बनाया

पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उन पर पुलिसकर्मियों ने इस बात के लिए दबाव बनाया कि वह लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। पीड़िता ने कहा कि जब मुझे थाने ले जाया गया तो वहां पुलिसवालों ने मुझ पर लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि हमारे बीच कोई गलत संबंध नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद पुलिसवालों ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस तुम लड़के के खिलाफ केस करा दो, क्योंकि वह मुस्लिम है। लड़की ने बताया कि उनके पास आर्य समाज की कोई महिला भी आई थी, जिसने कहा कि तुम हिंदू हो और लड़का मुसलमान है, तुम उससे कैसे शादी करोगी। पीड़िता ने ये भी बताया कि वह जब अपने दोस्त के घर पर थी, तब वहां शुरुआत में 12-16 लोग आए थे, लेकिन बाद में जब पुलिस आई, तब वहां बड़ी संख्या में लोग आ गए। लड़की और उसकी मां ने बताया कि थाने में भी बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे और वे उन पर दबाव बना रहे थे।

भीड़ के खिलाफ केस

पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जबकि 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। वहीं, एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने पुलिस वालों की इस हरकत को घोर कृत्य करार दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने न सिर्फ मारपीट की है बल्कि खुद ही वीडियो बनाकर वायरल भी किया है. उन्होंने बताया कि चारों सिपाहियों को को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वही चार लोग हैं, जो पुलिस वैन में पीड़ित लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इनमें हेड कांस्टेबल सलेख चंद, कांस्टेबल नीटू और महिला कांस्टेबल प्रियंका सिंह थे, जबकि एक होमगार्ड का जवान भी गाड़ी में मौजूद था, जिसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

ईरान से तेल आयात के प्रयास तो होगा बड़ा नुकसान : अमेरिका

वॉशिंगटन,(एजेंसी)। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर लगाए प्रतिबंधों से बचने के लिए विभिन्न देशों द्वारा 'विशेष भुगतान तंत्र' तैयार करने की कोशिश नुकसानदेह साबित होगी। अमेरिका का यह बयान उस वक्त आया है, जब यूरोपीय संघ ने इस्लामी देश के साथ कानूनी तौर पर व्यापार शुरू करने के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है।

गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन 2015 के ईरान परमाणु समझौते से हट गया था और उसने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध दोबारा लगा दिए थे। ईरान पर पहले चरण का प्रतिबंध पहले से ही लागू है, वहीं व्यापक प्रतिबंध चार नवंबर से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत सहित सभी देश उस वक्त तक ईरान से तेल का आयात बंद कर देंगे।

अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी देश ईरान से व्यापार करना जारी रखता है तो अमेरिकी बैंकिंग और आर्थिक तंत्र तक उसकी पहुंच ब्लॉक हो जाएगी। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रतिबंधों को लागू नहीं किया है और भारत की यह नीति रही है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही लागू करता है।भारत ईरान से तेल आयात करने वाले सबसे बड़े देशों में एक है और उसने तेल का आयात घटा दिया है, लेकिन उसकी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि वह आयात बंद कर दे।

भारत और अमेरिका इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को ईयू ने घोषणा की कि वह ईरान के साथ तेल और अन्य प्रकार के व्यापार को बरकरार रखने के लिए अमेरिका की दंडनीय कार्रवाई से बचने के लिए नया भुगतान तंत्र विकसित करेगा। ईयू के इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने मंगलवार को कहा, यह सर्वाधिक प्रतिकूल कदमों में से एक है।'

अमेरिका की दंडनीय कार्रवाई से बचने के लिए नया भुगतान तंत्र विकसित करेगा

भारत-बांग्लादेश ने साझेदारी पर जताई सहमति

ढाका, (एजेंसी)। भारत और बंगलादेश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने तथा बांग्लादेश के कम विकसित देश की श्रेणी से उन्नयन के लिए एक विस्तृत आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा दिए जाने पर सहमति जतायी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और बांग्लादेश के उनके समकक्ष तोफेल अहमद ने बुधवार को यहां आयोजित द्विपक्षीय बैठक में इस आशय का निर्णय लिया।

श्री प्रभु ने कहा कि यह साझेदारी भविष्य के लिए लाभदायक भी होगी और यह साकार भी होगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कुछ वर्षों में कम विकसित देश की श्रेणी से ऊपर का दर्जा हासिल कर लेगा जिसके लिए दोनों देशों के बीच व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय साझेदारी की आवश्यकता होगी। भारत और बंगलादेश के बीच व्यापारिक समझौता है और दोनों देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता के सदस्य हैं तथा भारत ने बंगलादेश के लिए ड्यूटी-फ्री और कोटा-फ्री आवागमन को मंजूरी दी है।

सेवाग्राम आश्रम पर कांग्रेस-बीजेपी में वर्चस्व की जंग

गांधी जयंती

नागपुर, (एजेंसी)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन (2 अक्टूबर) पर उनकी कर्मभूमि सेवाग्राम में कार्यक्रम आयोजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस को जहां 2 अक्टूबर को आश्रम के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है, वहीं बीजेपी उसी दिन आश्रम के ठीक सामने सभागृह में दुनिया का सबसे बड़ा चरखा स्थापित करने जा रही है।

इस दिन आश्रम में केवल प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति दी गई है जिसमें राज्य के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि बीजेपी सरकार के कार्यक्रम की योजना बहुत पहले बना ली गई थी और कांग्रेस का बैठक आयोजित करने का अनुरोध अंतिम समय पर आया है।

प्रशासन की दलील

वर्धा के डीएम शैलेष नावल ने कहा कि हम सबसे बड़ा चरखा बना रहे हैं जिसे वर्धा में स्थापित किया जाएगा। इसे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट बना रहे हैं और यह दिल्ली एयरपोर्ट पर लगे चरखे से बड़ा होगा जो इस समय सबसे बड़ा चरखा है। उधर, राज्य कांग्रेस के प्रमुख अशोक चव्हाण और यूथ कांग्रेस के प्रमुख सत्यजीत तांबे सेवाग्राम परिसर को बुक करने के लिए गए हैं। तांबे ने कहा, सेवाग्राम ट्रस्ट ने फैसला किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए हमने आश्रम के ठीक पास में अपना कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। यह प्रतिकात्मक है। हम सेवाग्राम ट्रस्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हम शांति मार्च निकालेंगे और राहुल गांधी एक बैठक को संबोधित करेंगे।

प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर सख्त हुए सीएम

लखनऊ,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से विभिन्न जिलों में हो रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार देर रात पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह को तलब किया और घटनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हुई बड़ी घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई। डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने हमीरपुर में शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव की घटना की जानकारी मिलने के बाद एडीजी इलाहबाद जोन को हमीरपुर में कैंप करने व उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया है। डीजीपी के अनुसार, शोभा यात्रा को कुछ लोग गैर परंपरागत मार्ग से निकालने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इसी बात को लेकर कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति बिगड़ी। घटना में एएसपी, सीओ व दो एसओ घायल हुए। बीते कुछ दिनों के भीतर प्रदेश में कई घटनाएं हुई हैं। इलाहाबाद में मंगलवार को दिनदहाड़े 22 लाख की लूट की घटना हुई। बांदा में टाइल्स व्यवसायी का अपहरण, प्रतापगढ़ में दोहरा हत्याकांड, बरेली में मोहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव की घटनाएं हुई, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने डीजीपी को तलब कर पूरी रिपोर्ट मांगी।

स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास बनेगा यूपी भवन, योगी ने रुपाणी को लिखा पत्र

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को पत्र लिखकर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास उत्तर प्रदेश भवन बनावाने के लिए जमीन आवंटित करने का आग्रह किया है। रुपाणी को भेजे गए पत्र में सीएम योगी ने लिखा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत यूपी सरकार को भूमि आवंटित की जाए, जिससे भव्य उत्तर प्रदेश भवन का निर्माण किया जा सके। हाल ही में सभी राज्यों को पत्र भेजकर जानकारी दी गई थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सभी राज्यों के भवन बनाए जाने के लिए जमीन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी का लोकार्पण करने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने 2013 में घोषणा की थी कि सरदार पटेल की दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा राज्य में स्थापित की जाएगी।

जर्मन कैथोलिक चर्च ने यौन उत्पीड़न पीड़ितों से माफी मांगी

फुल्डा,(एजेंसी)। जर्मनी की कैथोलिक चर्च ने पादरियों द्वारा यौन उत्पीड़न के हजारों पीड़ितों से माफी मांगी। साथ ही संस्थान के शीर्ष कार्डिनल ने अपराधियों को इंसाफ के कठघरे में खड़ा करने की बात कही। कार्डिनल राइनहार्ड मार्क्स ने कहा कि वह भरोसे को चकनाचूर करने वाले दशकों के उत्पीड़न और इतने लोगों द्वारा इनकी अब तक की गई अनदेखी पर शर्मिंदा हैं।

जर्मन बिशप्स कॉफ्रेंस के प्रमुख ने यह शर्मिंदगी तब जाहिर की जब संस्था ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि जर्मनी में 1946 और 2014 के बीच करीब 3,700 नाबालिगों, जिनमें ज्यादातर लड़के थे, का यौन उत्पीड़न किया गया। रिपोर्ट लिखने वाले शख्स ने कहा कि यह आंकड़ा तो पूरे आंकड़े का एक हिस्सा भर है। मैनहेम मनोवैज्ञानिक संस्थान के प्रोफेसर हेरल्ड ड्रेसिंग ने कहा कि कैथलिक चर्च में यौन दुर्व्यवहार एक सतत समस्या है और कोई ऐतिहासिक समस्या नहीं है। प्रफेसर ने बिशप्स कॉफ्रेंस की ओर से कराए गए शोध में समन्वय का काम किया था। बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही आयरलैंड के दौरे पर गए पोप फ्रांसिस ने भी चर्च में यौन शोषण की घटनाओं पर अफसोस जाहिर किया था।

संस्थान के कार्डिनल ने अपराधियों को इंसाफ के कठघरे में खड़ा करने की बात कही

मालदीव ने ब्रिटिश राज की मूर्तियां तोड़ीं

कोलंबो/ माले ,(एजेंसी)। मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने ब्रिटिश कालीन कुछ मूर्तियों को इस्लाम के लिए अपमानजनक बताया। इसके बाद पुलिस ने कुल्हाड़ी और अन्य उपकरणों की मदद से मंगलवार को उन्हें तोड़ दिया। यामीन ने जुलाई में ही इन मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन उसका पालन शुक्रवार को किया गया। जेसन डिकैरस टेलर द्वारा बनाई गई मूर्तियों को मालदीव के एक रिसॉर्ट में आधे डूबे हुए धातु के कंटेनर में रखा गया था। मालदीव का आधिकारिक धर्म इस्लाम मूर्ति निर्माण को प्रतिबंधित करता है। जुलाई में जब इन मूर्तियों को लगाया गया था तभी कुछ धर्मगुरुओं ने इसकी आलोचना की थी। हालांकि, इन मूर्तियों का इस्लाम से कोई नाता नहीं है।'कोरालारियम' सीरिज की इन मूर्तियों के खिलाफ लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने इन्हें नष्ट करने का फैसला लिया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जुलाई से अब तक इन मूर्तियों को नष्ट क्यों नहीं किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में यामीन की हार के तुरंत बाद इन्हें तोड़ा जा रहा है।

वतन वापसी चार अगस्त, 2014 को डीजल की तस्करी का आरोप लगाकर ईरान की नेवी ने गिरफ्तार कर लिया था

साथी को छुड़ाने नाविकों ने जुटाए जमानत के 46 लाख

अहमदाबाद ■ एजेंसी

गुजरात से एक सुखद खबर सामने आई है, जहां नाविकों ने ईरान में फंसे अपने साथी को वहां से निकालने के लिए जमानत राशि जुटाई है। कच्छ के मांडवी में रहने वाले 47 वर्षीय सलेह मोहम्मद ताईम सोमवार को चार साल बाद अपने वतन लौटे। परिवार और उनके मालिक के अलावा 250 से ज्यादा अन्य नाविकों ने भी उनकी जमानत की रकम जुटाई। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ताईम के लिए अजनबी हैं। सलेह के छोटे भाई इब्राहिम ने बीते सोमवार को उन्हें रिहा करवाया।

नाविकों ने 500 से लेकर 20 हजार रुपये तक का योगदान दिया और 11.5 लाख रुपये जमा किए। ईरान के नियमों के मुताबिक, सलेह मोहम्मद को रिहा करने के बदले कुल 46.50 लाख रुपये चुकाने की शर्त रखी गई थी। उनके पांच भाइयों वाले परिवार ने 15 लाख तो वहीं उनके मालिक ने 20 लाख रुपए दिए। इस तरह साथी नाविकों की मदद से ही यह राशि पूरी हो सकी।

कच्छ वाहनवता असोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कासम जफराबादी ने बताया कि ताईम के परिवार ने उनसे बताया था कि किस तरह वे लोग जरूरी रकम जुटाने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। उन्होंने यह बात मांडवी के एक प्रभावशाली नाविक अबू बकर पठान से बताई। जफराबादी ने बताया, पठान ने एक वॉट्सएप ग्रुप बनाया और सभी नाविकों को ताईम की मदद के लिए आगे आने की अपील करते हुए मेसेज किया। महज पांच घंटे में ही 11.50 लाख रुपये जुटा लिए गए।

ताईम के बड़े भाई नूर मोहम्मद ने कहा कि आखिरकार हमारा भाई वापस आ रहा है। हम सभी साथियों के शुक्रगुजार हैं कि उनकी मदद के चलते उमर अपनी पत्नी और चार बच्चों के पास लौट पाया है। ताईम को ईरान की नेवी ने 4 अगस्त, 2014 को गिरफ्तार कर लिया था जब दुबई से लौटते वक्त खराब मौसम की वजह से उन्हें ईरान के तट पर शरण लेनी पड़ी थी। उन पर डीजल की तस्करी और गलत तरह से प्रवेश का आरोप लगा था।

दुबई से लौटते समय खराब मौसम की वजह से पत्नी और चार बच्चों के साथ ईरान के तट पर शरण लेनी पड़ी थी

सूरत। सचिन आई.सी नायक प्राथमिक स्कुल में अतुल्य भारत दर्शन आयोजित कार्यक्रम में लोगो ने भाग लिया।

6 साल के बच्चे ने खोला माता की हत्या का राज, मृतका का पति गिरफ्तार

सूरत। शहर के पांडेसरा के गणेशनगर में विवाहिता की हत्या की गुत्थी उसके छह वर्षीय पुत्र के बयान से सुलझ गई और पुलिस ने बच्चे के पिता और मृतका के पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही तेज कर दी है। बता दें कि गणेशनगर में एक विवाहिता की हत्या हो गई थी। मृतका के पति का आरोप था कि पत्नी के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन मृतका के पुत्र ने अपनी माता की हत्या का राज खोल दिया।

सूरत में पांडेसरा के गणेशनगर में पत्नी नंदनी और दो संतानों के साथ रहनेवाले संजय ने पत्नी की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी अजय को फंसाने का पूरा प्रयास किया था। नंदनी की हत्या के बाद संजय ने पुलिस को बताया कि उसके नौकरी पर चले जाने के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी घर आया। जहां अजय और नंदनी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। इसी दौरान अजय ने आवेश में आकर नंदनी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि घटना के वक्त नंदनी का प्रेमी अजय मौका ए वारदात के आसपास नहीं था। संजय ने पुलिस को बताया था कि घटना की खबर मिलते ही वह रात करीब साढ़े बारह बजे घर लौट आया और ए ब्युलैंस 108 के जरिए नंदनी को अस्पताल ले गया। जबकि उसके मोबाइल की जांच में पता चला कि रात 2.05 बजे संजय ने ए ब्युलैंस को फोन किया था। यदि नंदनी घायल थी तो संजय डेढ घंटे तक घर में क्या करता रहा ? संजय के कार्यस्थल पर पुलिस जांच में पता चला कि संजय उस रात नौकरी पर ही नहीं गया। रात करीब साढ़े नौ बजे संजय ने कंपनी में फोन कर कहा कि उसकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वह आज नहीं आएगा। संजय ने पुलिस को बताया कि अजय ने जब नंदनी को मारा तब उसके बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। लेकिन पडौसियों ने किसी के रोने की आवाज सुनी होने से इंकार कर दिया। नंदनी को अस्पताल पहुंचाने में भी संजय ने पडौसियों की मदद नहीं ली। जिससे पुलिस का उस पर संदेह पु ता हो गया। इस संदेह को संजय के पुत्र के बयान ने और ज्यादा मजबूत कर दिया। जिसमें उसने कहा कि मैं घर में सो रहा था, तब पापा ने मुझे जगाया और बताया कि अजय तेरी मां की हत्या कर फरार हो गया है। इन सब तथ्यों के सामने आने के बाद संजय ने नंदनी की हत्या की बात कबूल कर ली।

सूरत शहर पर गंभीर रोग का प्रकोप: वाइन फ्लू इंचार्ज डॉ. उपाध्याय सूरत पहुंचे

सिविल, स्मीमेर और पालिका के स्वास्थ्य विभाग के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग: रोगों को अंकुश में लेने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही किये जाने का निर्देश

सूरत, बारिश के विदाई के दिन शुरु होने के साथ शहर पर गंभीर रोगों की छाया मंडरानी शुरु हो गई है। स्वाइन फ्लू के मामलो में क्रमश: वृद्धि हो रही है। ऐसे में राज्य के स्वाइन फ्लू इंचार्ज डॉ. उपाध्याय आज सूरत का आकस्मिक मुलाकात पर आ पहुंचे। जिन्होंने सरकारी तथा नीजी चिकित्सको के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की। शहर में मच्छरजन्य रोगों का उपद्रव काफी बढ गया है। शहरभर की हॉस्पिटलों में मलेरिया, डेंग्यु के अलावा फ्लू के मामले बढ गये हैं। ऐसे में रोगों को नियंत्रण में लेने हेतु स्वास्थ्य विभाग की दौडधाम बढ गई है।

सूरत शहर में पिछले कई दिनों से विविध रोगों को लेकर शिकायत हो रही है। जिसमें खास करकेरांदेर जोन में डेंग्यु, मलेरिया जैसे मच्छरजन्य रोगों के अलावा वायरल के मामले बढ गये हैं। इस संदर्भ में गत रोज डिप्युटी मेयर निरव शाह ने पालिका के स्वास्थ्य विभाग की क्लास ली थी और रिपोर्ट मांग तात्कालिक कार्यवाही करने का आदेश दिया था। इसके अलावा उधना-लिंबायत, अठवा, कतारगाम, वेड-डभोली, वराछा के सरसाणा, पूणा, सेन्ट्रल जोन के कई क्षेत्रों में वायरल तथा डेंग्यु के केस बढ जाने की जानकारी मिली है। हलांकि ऐसे आक्षेप किये जा रहे हैं कि तंत्र वास्तविक आंकडे छिपा रहा है। वास्तव में रोगों की स्थिति गंभीर हो गई है। दूसरी ओर जानलेवा स्वाइन फ्लू ने सूरत शहर में सिर उठाया है। पिछले कई सप्ताह में स्वाइन फ्लू के अनेक मामले सामने आये हैं। तंत्र क आंकडे देखे तो अब तक स्वाइन फ्लू के 36 मामले पॉजिटीव आये हैं और संदिग्ध मामलों में भी सतत वृद्धि हो रही है।

जिसके कारण राज्यके स्वाइन फ्लू इंचार्ज और अहमदाबाद की बी.जे. हॉस्पिटल के डीन डॉ. कमलेश उपाध्याय आज अचानक ही सूरत आ पहुंचे। डॉ. उपाध्याय ने सिविल और स्मीमेर हॉस्पिटल की मुलाकात ली। इसके अलावा सूरत महानगरपालिका में डॉ. उपाध्याय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें पालिका के स्वास्थ्य विभाग क चिकित्सकों तथा तकनीकी स्टाफ, सिविल हॉस्पिटल के करीब पांच हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट चिकित्सक, स्मीमेर के अग्रणी चिकित्सक हाजिर रहे। स्वाइन फ्लू के अलावा मच्छरजन्य अन्य रोगों को अंकुश में लेने के लिए की जा रही कार्यवाही की डॉ. उपाध्याय ने समीक्षा की और आवश्यक सूचन दिये। खास करके जानलेवा स्वाइन फ्लू को अंकुश में लेने के लिए जनजागृति अभियान वेगवान बनाने का निर्देश दिया।

6 साल के बच्चे ने खोला माता की हत्या का राज, मृतका का पति गिरफ्तार

सूरत, शहर के पांडेसरा के गणेशनगर में विवाहिता की हत्या की गुत्थी उसके छह वर्षीय पुत्र के बयान से सुलझ गई और पुलिस ने बच्चे के पिता और मृतका के पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही तेज कर दी है। बता दें कि गणेशनगर में एक विवाहिता की हत्या हो गई थी। मृतका के पति का आरोप था कि पत्नी के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन मृतका के पुत्र ने अपनी माता की हत्या का राज खोल दिया।

सूरत में पांडेसरा के गणेशनगर में पत्नी नंदनी और दो संतानों के साथ रहनेवाले संजय ने पत्नी की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी अजय को फंसाने का पूरा प्रयास किया था। नंदनी की हत्या के बाद संजय ने पुलिस को बताया कि उसके नौकरी पर चले जाने के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी घर आया। जहां अजय और नंदनी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। इसी दौरान अजय ने आवेश में आकर नंदनी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि घटना के वक्त नंदनी का प्रेमी अजय मौका ए वारदात के आसपास नहीं था। संजय ने पुलिस को बताया था कि घटना की खबर मिलते ही वह रात करीब साढ़े बारह बजे घर लौट आया और एम्ब्युलैंस 108 के जरिए नंदनी को अस्पताल ले गया। जबकि उसके मोबाइल की जांच में पता चला कि रात 2.05 बजे संजय ने एम्ब्युलैंस को फोन किया था7 यदि नंदनी घायल थी तो संजय डेढ घंटे तक घर में क्या करता रहा? संजय के कार्यस्थल पर पुलिस जांच में पता चला कि संजय उस रात नौकरी पर ही नहीं गया। रात करीब साढ़े नौ बजे संजय ने कंपनी में फोन कर कहा कि उसकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वह आज नहीं आएगा। संजय ने पुलिस को बताया कि अजय ने जब नंदनी को मारा तब उसके बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। लेकिन पडौसियों ने किसी के रोने की आवाज सुनी होने से इंकार कर दिया। नंदनी को अस्पताल पहुंचाने में भी संजय ने पडौसियों की मदद नहीं ली। जिससे पुलिस का उस पर संदेह पुख्ता हो गया। इस संदेह को संजय के पुत्र के बयान ने और ज्यादा मजबूत कर दिया। जिसमें उसने कहा कि मैं घर में सो रहा था, तब पापा ने मुझे जगाया और बताया कि अजय तेरी मां की हत्या कर फरार हो गया है। इन सब तथ्यों के सामने आने के बाद संजय ने नंदनी की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने नंदनी की हत्या के आरोप में संजय को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी।

आयकर विभाग ने 50 वर्ष पहले के मामलों में शुरु की रिकवरी

सूरत,आयकर विभाग ने जारी वित्तीय वर्ष में सर्वे और सर्च की बजाय पिछले मामलों में रिकवरी करके लक्ष्य हांसिल करने का प्रयास शुरु किया है। हाल ही में पांच-सात वर्ष पहले के मामलों में करोडो रुपये की रिकवरी के बाद अब आयकर विभाग ने 50 वर्ष पूर्व के मामलों में रिकवरी के प्रयास शुरु किये हैं।

आयकर विभाग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग सूरत कमिश्नरेट में पिछले दो वर्ष से अधिकारियों द्वारा सर्वे और सर्च की कार्यवाही बेहद कम कर दी गई है। उसके सामने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आयकर विभाग द्वारा रिकवरी की कार्यवाही शुरु की गई है। एक सप्ताह पहले ही विभाग ने एक बिल्डर के यहां सात वर्ष पहले की दो करोड की बकाया रकम में से एक करोड की वसूली की थी। अब विभाग ने पचास वर्ष पहले के मामलों में भी नोटिश भेजने की शुरुआत की है।

हलांकि अधिकांशत: मामलों में करदाता नहीं मिलने से नोटिश वापस आ रही है तो कई मामलों में रिकवरी भी हो रही है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि इतना वर्षो बाद शुरु की गई कार्यवाही में सफलता मिलने की संभावना कम है लेकिन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्स के निर्देश अनुसार वे तमाम पेंडिंग मामलों में नोटिश भेज मिल्कत भी अटेच करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

कई मामलों में तो आयकर विभाग द्वारा प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही भी शुरु की गई है। उलेखनीय है कि आयकर विभाग के नये कानून के अनुसार यदि सर्च और सर्वे की कार्यवाही दौरान किसी के यहां से काला धन पकडा जाता है तो टेक्स के साथ कुल 116 प्रतिशत रकम की वसूली की जायेगी और यदि करदाता डिस्क्लोजर करे तो टेक्स के साथ 86 प्रतिशत रकम चुकानी होगी। ऐसे कडे कानून के कारण आयकर अधिकारी सर्वे और सर्च से अधिक रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं।

जमीन में निवेश के नाम पर एक करोड की ठगी

सूरत, सरथाणा जकातनाका क्षेत्र में रहनेवाले दंपत्ति ने पूणा के युवक को बातों में बहलाकर कोसंबा में जमीन में निवेश का लालच देकर उसके पास एक करोड रुपये ले लिये। हलांकि बाद में दंपत्ति ने तमाम रुपये अपने नीजी उपयोग में लेकर हजम कर लिया। जमीन या पैसा दोनों में से कुछ नहीं मिलने पर युवक ने वराछा पुलिस में दंपत्ति और उनके पुत्र के खिलाफ एक करोड रुपये ठगी की शिकायत दर्ज कराई।

घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार पूणा-कुंभारिया रोड एसएमसी स्टोर्स समीप स्थित सिलिकोन पैलेस में रहनेवाला रोहित कांतिलाल कारवडीया कमीशन एजेन्ट का व्यवसाय करता है। सरथाणा जकातनाका वैभव बंग्लोज में रहनेवाले जगदीशभाई डुंगरभाई सावलिया रोहित के संपर्क में आया। जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जगदीश आयेदिन रोहित को वराछा रोड मीनी बाजार स्थित प्रीन्सेस प्लाजा में अपनी ऑफिस पर बुलाता था। इस दौरान जगदीश ने रोहित को कोसंबा में जमीन में निवेश करने का लालच दिया। रोहित भी जगदीश की बातों में आ गया। रोहित कई बार कोसंबा के नंदाव में जमीन के लिए जगदीश को पैसे जमा कराता रहा। दो वर्ष में करीब एक करोड रुपये जगदीश और उसकी पत्नी नीता और पुत्र हार्दिक को दे दिये। जिसके बाद जगदीश ने न तो जमीन दी और न ही रुपये। रुपये की उगाही करने पर जगदीश ने हाथ उंचे कर दिये। जिससे रोहित ने गत रोज वराछा पुलिस में दंपत्ति और उसके पुत्र के खिलाफ एक करोड रुपये की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की जांच कार्यवाही कर रही है।

किसानों के विरोध को लेकर दोगुना मुआवजा की घोषणा

गांधीनगर। प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट बुलेट ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भूमि अधिग्रहण को लेकर उठे किसानों के विरोध की वजह से सरकार ने दोगुना मुआवजा की घोषणा की है।

राजस्व मंत्री कौशिक पटेल की घोषणा के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए चार गुना मुआवजा भरपायी करेगी। जबकि शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करनेवाले लोगों को दोगुना मुआवजा देने की घोषणा की गई है। भूमि की मूल कीमत के २५ फीसदी ज्यादा देने की घोषणा राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने की है। राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने मीडिया के साथ सरकार ने लिए निर्णयों की की जानकारी देते हुए कहा है कि, बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए शामिल हो रहे गांवों ने राज्य सरकार से ज्यादा मुआवजा चुकाने के लिए पेशकश की थी। उनकी यह पेशकश को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है।

जवाहरनगर थाने के पीएसआई 30 हजार की रिश्वत लेते धरे गए

वडोदरा। एन्टी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शहर के जवाहरनगर थाने के पीएसआई को रु. 30000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

जानकारी के अनुसार वडोदरा के जवाहरनगर पुलिस ने कोयली गांव निवासी उपेन्द्र उर्फ राकेश को शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में महेश नामक शख्स को पुलिस ने वांटेड घोषित किया था। गिरफ्तार उपेन्द्र उर्फ राकेश को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया था। बाद में जवाहरनगर थाने के पीएसआई इंद्रजीतसिंह महेन्द्रसिंह सरवैया ने आरोपी राकेशख्से मारपीट नहीं करने के एवज में रु. 30000 की रिश्वत मांगी थी। जबकि वांटेड आरोपी महेश को हाजिर करने और उसे परेशान नहीं करने के एवज में रु. 400000 की रिश्वत की मांग की थी। आरोपी ने एसीबी से इसकी शिकायत कर दी। एसीबी ने जाल बिछाकर जवाहरनगर थाने के पीएसआई इंद्रजीत सरवैया को रु. 30000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

गुजरात की 6 अन्य तहसीलें सूखा प्रभावित घोषित

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने कच्छ के बाद राज्य के अन्य तीन जिलों की 6 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। राजस्व मंत्री कौशिक पटेल की अध्यक्षता में उप समिति की सूखा के मुद्दे पर आज गांधीनगर में बैठक हुई। जिसमें जारी वर्ष में हुई अपर्याप्त बारिशख्सर चर्चा की गई। जारी वर्ष में राज्य की 251 तहसीलों में से अब तक कच्छ की 10 तहसीलों में 111 मिमी बारिश हुई है। जबकि बनासकांठा के वाव, सूईगाम, कांकरेज और थराद में 125 मिमी से कम बारिश हुई। पाटण के चाणस्मा और अहमदाबाद के मांडल में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। उप समिति की बैठक में इन तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। 1 अक्टूबर से कच्छ जिला समेत बनासकांठा, पाटण और अहमदाबाद की छह तहसीलों में जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। समिति में रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की गई। राजस्व मंत्री का दावा है कि सूखा संबंधी चर्चा और समीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उप समिति समेत जिलास्तर पर समिति का गठन किया है।

12.85 लाख की विदेशी शराब समेत एक शख्स गिरफ्तार

राजकोट। एलसीबी पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर गोंडल के भुणावा गांव की सीमा से एक शख्स को रु. 12.85 लाख कीमत की विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार राजकोट एलसीबी पुलिस की टीम गश्त पर थी। उस वक्त सूचना मिली कि गोंडल तहसील के भुणावा की सीमा स्थित हार्दिकसिंह गिरीराजसिंह जाडेजा की वाडी में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब उतारी गई है। सूचना के आधार पर एलसीबी की टीम ने जाडेजा की वाडी में छापा मारकर गोंडल के सहजानंदनगर निवासी भरत भीखाभाई जादव नामक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही रु. 1285200 कीमत की 2544 विदेशी शराब समेत कुल रु. 1436200 का माल जब्त कर लिया।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

शराब के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल : भाजपा सांसद

अहमदाबाद। अक्सर विवादों में रहनेवाले पंचमहल निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रभातसिंह चौहाण एक बार फिर विवादित बयान देकर सूर्खियों में आ गए हैं। प्रभातसिंह चौहाण ने एक कार्यक्रम में कहा कि वाईन के बगैर चुनाव जीतना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैंने शराब नहीं देखी। चौहाण ने कहा कि भले ही उनकी आयु 77 वर्ष है, लेकिन आगामी 3 टर्म तक लोकसभा का चुनाव लडूंगा। पंचमहल में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने शराब से संबंधित बयान को लेकर प्रभातसिंह से सवाल किया तो वह टाल गए। गौरतलब है प्रभातसिंह चौहाण पहले भी ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं। पंचमहल जिले में पंचायत चुनाव के दौरान भी प्रभातसिंह चौहाण ने दावा किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ कोई उ मीदवार नहीं होगा। प्रभातसिंह ने दावा किया कि वर्ष 2019, 2025 और वर्ष 2030 तक सांसद रहेंगे। आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरा टिकट काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com